न्यू दलित, न्यू इंडिया

-लेखक - गुरु प्रकाश (सहायक प्रोफेसर, पटना विश्वविद्यालय)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (सामाजिक न्याय) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

04 जनवरी, 2021

आकांक्षा और अभिकथन समुदाय की उभरती राजनीति के मूल में स्थित हैं।

भारत में दलितों पर बहस में आज कई परतें निहित हैं। इसे अब सकारात्मक कार्रवाई, संरक्षण और प्रतीकात्मकता की राजनीति के नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। दलित विचार बदलते सामाजिक आख्यानों और राजनीतिक परिदृश्य के साथ विकसित हुआ है। वर्तमान संदर्भ में दलित को समझने के लिए दो मुद्दे हैं। एक आकांक्षाओं और अभिकथन से सम्मिलित है और दूसरे को आक्रामकता और समायोजन के प्रतिमानों के भीतर अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है।

गुजरात में जिग्नेश मेवाणी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का उद्भव जोर-शोर से हुआ, जबकि मिलिंद कांबले, टीना डाबी और कनिष्क कटारिया की कहानियाँ समकालीन दलित संघर्ष के आकांक्षी घटक का प्रतिनिधित्व करती हैं। हर कहानी उल्लेखनीय है और दलित दिमाग पर कब्जा करने का क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक रूप से खुला है।

ये व्यक्तिगत उदाहरण हैं लेकिन संस्थागत स्तर पर गहरा इतिहास रचा जा रहा है। मिलिंद कांबले विशेष उल्लेख के हकदार हैं क्योंकि उन्होंने अपने संगठन, दलित इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (DICCI) के माध्यम से देश भर से 5,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु, मध्यम और मेगा दलित उद्यमियों का एक नेटवर्क बनाया है। ये ब्लैक कैपिटलिज्म या अश्वेत पूँजीवाद के अमेरिकी विचार से प्रेरित थे और अक्सर इस बात पर टिप्पणी करते हुए पाए जाते हैं कि बराक ओबामा के उदय से पहले भी कई सौ अश्वेत उद्योगपति प्रभावशाली थे।

अगर हम मुद्रा योजना पर ध्यान दें, तो पाएंगे कि यह एक गेम-चेंजर योजना है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस योजना से अनुसूचित जाति के लाभार्थी 61.14 लाख और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी 16.78 लाख हैं और दोनों को मिलाकर कुल लाभार्थी 77.92 लाख हैं। ये लाभार्थी कुल 22.34 प्रतिशत हैं और संवितरण राशि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 19,433 करोड़ रुपये है। कांबले ने दलित युवकों से "नौकरी करने वाली नहीं, नौकरी देने वाले" बनने की मांग की है। वे बाबासाहेब अम्बेडकर से प्रेरित हैं, जो उद्यमिता के प्रबल समर्थक भी थे। अर्थशास्त्र में उनकी छात्रवृत्ति इस विचार का प्रमाण है कि जाति को हराने में पूंजी का कितना महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।

प्रतिनिधित्व न्यू दलित विचारधारा की एक और महत्वपूर्ण आधारशिला है। आजादी के 70 साल बाद भी आज तक एक भी कैबिनेट सचिव या एक विदेश सचिव किसी अनुसूचित जाति वर्ग से नहीं बना है, जो संयोग की बात नहीं है। कुलपति, प्रोफेसर, थिंक टैंकरों और लेखकों की संख्या एक और दुखद कहानी है। विश्वविद्यालयों में रोस्टर प्रणाली का प्रतिरोध प्रतिनिधित्व के इस संघर्ष का सबूत था। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर दिए गए प्रतिकूल निर्णय को सुधारने के लिए सरकार को आखिरकार अध्यादेश लाना पड़ा।

उच्च न्यायपालिका अभी तक एक और गंतव्य है जो प्रतिनिधित्व के पैमाने पर बहुत कम स्कोर करती है। शीर्ष अदालत में 2010 से एक भी दलित न्यायाधीश नहीं आया है। निचली न्यायपालिका में वैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण के बावजूद, बेंच में हाशिए पर स्थित जातियों के लिए जगह सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों, दलितों की

निराशाजनक उपस्थिति को दर्शाते हैं। न्यूज रूम में दलितों की अनुपस्थिति सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसी जगहों पर दृष्टिकोण की विविधता महत्वपूर्ण है, जहां राय बनाई जाती है।

अगली पीढ़ी के संघर्ष को विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व की मांग से परिभाषित किया जाएगा। यह विशेष रूप से संविधान के माध्यम से नहीं, बल्कि चेतना और आत्म-सुधारात्मक उपायों के क्रमिक विकास से होगा। उदाहरण के लिए, DICCI और Tata Corporation ने एक साथ मिलकर सकारात्मक कार्रवाई की योजना बनाई है, जिसके माध्यम से वे दलित उद्यमियों का समर्थन करेंगे। बात यहीं नहीं रुकती। एक बार जब वे प्रशिक्षित हो जाते हैं, तो उन्हें अपने स्वयं के उपक्रमों के साथ शुरू करने के लिए निधि सहायता प्रदान की जाती है, जब तक कि वे अंततः टाटा व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल नहीं हो जाते।

न्यू दलित अब एक हितधारक और न्यू इंडिया कहानी में एक सक्रिय भागीदार बनने की लड़ाई के लिए तैयार है। उसे अब और सताया नहीं जा सकता। सत्ता की पुरानी संरचनाएं चरमरा रही हैं। ऊर्जा और उत्साह की ताजा लहर एक सकारात्मक दिशा में दलित कथा का मार्गदर्शन करेगी और एकीकरण के विचारों को स्पष्ट करेगी।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. इसकी शुरुआत गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु / सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
2. इस योजना के तहत सबसे अधिक 20 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जायेंगे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 2 **(b)** 1 और 2 दोनों
(c) केवल 1 **(d)** न तो 1 न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in the context of Pradhan Mantri Mudra Yojana:-

1. It has been started with the objective of providing loans up to 10 lakh to non-corporate, non-agricultural small / micro enterprises.
2. Maximum loans up to Rs 20 lakh will be provided under this scheme.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 2 **(b)** Both 1 and 2
(c) Only 1 **(d)** Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. भारत की जाति व्यवस्था में व्याप्त खामियों पर प्रकाश डालते हुए अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु संविधान में वर्णित प्रावधानों पर चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Q. While discussing the provisions mentioned in the Constitution for the upliftment of Scheduled Castes, highlight the flaws in the caste system of India. (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।